



संपादकीय

राहुल के बयान का निहितार्थ

चुनाव अभियान के मध्य में राहुल गांधी से यह अपेक्षा तो नहीं की जा सकती थी कि वे 16 मई के बाद सरकार बनाने के लिए तीसरे मोर्चे को समर्थन देने की बात खुलेआम कहते। ऐसा कहने का मतलब यह होता कि नतीजा आने के पहले ही कांग्रेस के कमांडर ने हार मान ली है। बहरहाल, राहुल गांधी से यह सवाल उतनी शिद्दत से नहीं पूछा जाता, अगर उनकी पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से संभावित तीसरे मोर्चे के समर्थन का एलान नहीं कर चुके होते। ऐसा नहीं हुआ होता तो राहुल गांधी की बेलाग टिप्पणी को सामान्य राजनीतिक वक्तव्य के रूप में देखा जाता। किंतु, इस मुद्दे पर पार्टी से दो अलग-अलग राय निकली हैं, इसीलिए ऐसी अटकलों को बल मिला है कि कांग्रेस के भीतर चुनाव बाद की स्थितियों को लेकर सोच की दो तरह की धाराएं हैं। बताया जाता है कि एक धारा पुराने अथवा सोनिया गांधी के दौर में शक्तिशाली रहे नेताओं की है जो भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को केंद्रीय सत्ता में आने से रोकने के लिए हर तरह की जोड़-तोड़ के पैंरोकार हैं अथवा वे भावी सरकार में कांग्रेस की भूमिका बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी धारा राहुल गांधी के समर्थकों की बताई जाती है। संकेत यह है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा कांग्रेस संगठन है। उनकी रुचि पार्टी की जड़ें फिर से जमाने में है। इसके लिए विपक्ष में बैठना पड़े तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। राजनीति में पारदर्शिता, पार्टी में अंदरूनी जनतंत्र और वंचित तबकों के सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की इन दोनों अंदरूनी धाराओं के बीच मतभेद पहले भी सार्वजनिक हुए हैं। इसीलिए तीसरे मोर्चे को समर्थन न देने के राहुल गांधी के कथन को सामान्य राजनीतिक बयान से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इससे तीसरे मोर्चे का गुंबारा फुला रहे वामपंथी और कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं को अवश्य निराशा होगी। हकीकत यही है कि नीति और कार्यक्रमों के आधार पर किसी तीसरे मोर्चे का अस्तित्व फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए जारी कयास को सत्ता का समीकरण बैठाने की कोशिश से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव के बाद सीटों की संख्या किस तरह के समीकरणों का रास्ता खोलेंगी, अभी साफ नहीं है। मगर राहुल गांधी ने सत्ता की राजनीति को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर अच्छा किया है।

बात पते की

ज्ञानी व्यक्ति शत्रु से प्यार करने के काबिल तो हो ही, वह मित्र से नफ़रत करने में भी सक्षम होना चाहिए। -फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक

जीने की राह

बहुत काम करने के बाद थकान स्वाभाविक है, लेकिन कभी-कभी अकारण थकान आ जाती है। लगता है जैसे शरीर कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है। आराम के बाद भी थकान सी बनी रहती है। ऐसी अकारण थकान आए तो सावधान हो जाए, क्योंकि इसका अगला चरण उदासी और उसका अगला चरण डिप्रेशन होगा। असल में देखा जाए तो अकारण कुछ नहीं होता। ऐसा तब होता है जब जिंदगी में कोई दुख आ जाता है। ऐसा दुख जिसकी कल्पना भी न की गई हो। उसका भीतर मंथन चलता है तो अकारण थकान महसूस होती है। परिश्रम की अति और आराम की भी अति में शरीर थकता है। मनुष्य के जीवन में दो अतियां जरूर आती हैं - एक जन्म, दूसरा मृत्यु। हम जन्म पर अति की सीमा तक टिके हुए हैं और



घोषणा

बीच चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के वादे से पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा होगा

कांग्रेस का आत्मघाती कदम

ने हाल ही में पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण

के वादे के साथ सारे दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा किया है। इसे पार्टी का उप घोषणा-पत्र कहना होगा, जो आधे चुनाव हो जाने के बाद आया है। साफ है कि मुस्लिम वोट आकर्षित करने की कांग्रेस की नीति में न तो समय का ध्यान रखा गया है और न यह घोषणा सुनियोजित योजना का हिस्सा नजर आती है। इससे कांग्रेस को मुस्लिम वोट इसके हक में जुटाने में शायद ही कोई मदद मिले। कई राज्यों में जहां भाजपा मजबूत होकर उभर रही है, मुस्लिम ऐसे दल या गठबंधन को वोट देना चाहेंगे, जो भाजपा के प्रत्याशी को हारने में सक्षम हो।

उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां मुस्लिम काफी बड़ी तादाद में हैं (उत्तरप्रदेश में 18.5 और बिहार में 16.5 फीसदी) और कई चुनाव क्षेत्रों में नतीजे प्रभावित करने में सक्षम हैं, मुस्लिम कांग्रेस को इस लिए वोट नहीं देंगे, क्योंकि वह भाजपा को हाराने की स्थिति में नहीं है। उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट आकर्षित करेंगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल (यू) को मुस्लिम वोट मिलेंगे। हालांकि राजद से गठबंधन के कारण कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है।

कांग्रेस को आरक्षण के वादे से असम में फायदा हो सकता था, जहां मुस्लिम काफी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन पार्टी की घोषणा देर से आई। जिस समय यह घोषणा आई तब तक आधे चुनाव क्षेत्रों में मतदान हो चुका था। पश्चिम बंगाल (25 फीसदी मुस्लिम वोट) में भी मुस्लिम वोट नतीजों प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहां चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नजर नहीं आती। चुनावी टक्कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच है। फिर राज्य के मुस्लिमों में भाजपा का भय उतना नहीं है, क्योंकि वहां भाजपा कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है।

कांग्रेस को आरक्षण की घोषणा का फायदा झारखंड, कर्नाटक या दिल्ली में मिल सकता था, जहां मुस्लिम कुल मतदाताओं के 12 से 14 फीसदी हैं। पर इन राज्यों के लिए भी घोषणा देरी से आई। गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्यप्रदेश में कांग्रेस की घोषणा के बाद मतदान हुआ पर वहां मुस्लिमों की इतनी संख्या नहीं है कि वे नतीजों पर असर डाल सकें।



मुस्लिम वोट दिलाने में कांग्रेस की मदद करने की बजाय, इस नई रणनीति का उलटा ही असर होगा और कांग्रेस को जितना फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। यह सही है कि जब मुस्लिमों से आरक्षण का वादा किया गया तो उत्तरप्रदेश, बिहार और गुजरात में ऐसी सीटों की बड़ी संख्या थी, जिनके लिए मतदान होना था। हालांकि, यह भरोसा होना कठिन है कि कांग्रेस उत्तरप्रदेश में मुस्लिम वोटों का रुझान अपने फायदे में मोड़ सकेगी, जहां मुस्लिम परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी या कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी को वोट देते रहे हैं। बिहार में मुस्लिम राजद-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन इसका असली फायदा राजद को होगा, जो 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक सीट उसने अपनी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दी है।

कांग्रेस द्वारा ऐसी घोषणा को आत्मघाती गोल ही कहा जाएगा। इसका फायदा होने की बजाय नुकसान इसलिए होगा, क्योंकि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मतदाता नाराज हो जाएंगे। वजह यह है कि प्रस्तावित नीति में मुस्लिमों को 4.5 फीसदी कोटा ओबीसी के मौजूदा 27 फीसदी कोटे में से दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनावों में ओबीसी ने कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट नहीं दिया है। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद से केवल 2.5 फीसदी ओबीसी मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिए हैं। इस वर्ग ने बिहार में राजद या जद (यू), उत्तरप्रदेश में सपा, उड़ीसा में बीजद या आंध्र में तेलुगू देशम पार्टी और कर्नाटक में जद (एस) को बड़ी संख्या में वोट दिए हैं।

यहां तक कि मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की भाजपा से

जीवन दर्शन

चंद्रशेखर आजाद के क्रांति दल का कोई ठोस आर्थिक खेत नहीं था। इसलिए दल की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत नहीं थी। एक बार जब धन की सख्त आवश्यकता महसूस हुई तो कानपुर में दल की कार को बेचने का प्रयास में लग गए। उन्हीं दिनों आजाद की माता की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्हें रोजाना भोजन भी नसीब नहीं होता था। आजाद अपनी मां की इस दशा से वाकिफ थे, किंतु देश की चिंता करने वाले आजाद के पास परिवार की चिंता करने का वक्त ही नहीं था। किसी ने यह बात ख्यात समाज सुधारक गणेशशंकर विद्यार्थी को बताई। उन्होंने आजाद को बुलाया और उन्हें दो सौ रुपए देते हुए कहा कि ये अपनी मां को दे दो, ताकि उनके भोजन-पानी का उचित प्रबंध हो सके। किंतु आजाद ने वे रुपए पार्टी के कामों में व्यय कर

सीधी टक्कर है, पार्टी ओबीसी मतों को आकर्षित नहीं कर पाई है। उसके हक में एक-तिहाई से थोड़े ज्यादा वोट आए जबकि ज्यादातर ओबीसी वोट भाजपा को मिले हैं। सीएसडीएस के चुनाव पूर्व सर्वे से भी ओबीसी वर्ग में कांग्रेस का आधार बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि सिर्फ 24 फीसदी ओबीसी मतदाताओं ने ही कांग्रेस को वोट देने का इशारा दिया है। इसके विपरीत 35 फीसदी ने भाजपा को वोट देने की बात कही जबकि शेष क्षेत्रीय दलों के पक्ष में नजर आए।

इसी प्रकार दलित अल्पसंख्यकों तक अनुसूचित जाति के दायरे का विस्तार भी कांग्रेस को नुकसान ही ज्यादा पहुंचाएगा। कांग्रेस ने आरक्षण की जो नीति रखी है वह दलितों के मौजूदा कोटे को कम करेगी। जहां कांग्रेस फिलहाल तो ऐसे कोई नीतिगत बदलाव लाने की स्थिति में नहीं दिखाई देती है पर इस घोषणा से इसने दलित मतदाताओं के बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है। इससे विभिन्न राज्यों में पहले से ही कम हो रहे दलित आधार को कांग्रेस और भी खो देगी। सीएसडीएस की ओर से कराए अध्ययन से संकेत मिले हैं कि कांग्रेस अपने दलित समर्थक, क्षेत्रीय या प्रादेशिक दलों के हक में खो चुकी है। अब कांग्रेस दलित वोटरों के लिए पहला विकल्प नहीं रही है।

अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो 30 फीसदी से भी कम दलित मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी टक्कर क्षेत्रीय दलों से है, वहां तो दलित मतों में इसकी हिस्सेदारी 22-23 फीसदी तक गिर गई है। कांग्रेस के इस नुकसान का भाजपा को फायदा नहीं होता, क्योंकि पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में सिर्फ 10-12 फीसदी दलितों ने ही भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। दलित वोट सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। पिछले कुछ आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर 21 फीसदी दलितों ने बसपा को वोट दिया है। सीएसडीएस द्वारा कराए सर्वे में भाजपा और क्षेत्रीय दलों के पक्ष में दलित समर्थन का कुछ झुकाव देखा गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद ही कोई आकर्षण है।

यदि कांग्रेस ऐसी किसी नीति को लेकर गंभीर है तो यह प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू हो जानी थी। कम से कम इसे घोषणा-पत्र में तो जगह मिलनी चाहिए थी। चुनाव के बीच में ऐसी घोषणा यही बताती है कि कांग्रेस के भीतर किस तरह बिना सोचे-विचारे निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस की यह पहल तो इसी उक्ति को साबित करती है, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि।'

जीवन दर्शन

देश के लिए की मां की अनदेखी

दिए। जब विद्यार्थीजी से आजाद की अगली बार भेंट हुई तो उन्होंने माताजी को रुपए भेजने की सस्दीक करनी चाही। तब आजाद ने कहा, 'उस बूढ़ी के लिए पिस्तौल की दो गोलियां काफी हैं। विद्यार्थीजी इस गुलाम देश में लाखों परिवार ऐसे हैं, जिन्हें एक समय की रोटी नसीब नहीं होती। मेरी माता दो दिन में एक बार तो भोजन पा ही जाती है। वे भूखी रह सकती हैं, किंतु पैसे के लिए पार्टी के सदस्यों को भूखा नहीं मरने दूंगा। उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मेरी माता- भूखी पर भी जाएं तो उससे देश को कोई हानि नहीं होगी।' विद्यार्थीजी आजाद की यह भावना देख नतमस्तक हो गए। भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचे आज के भारतवर्ष के लिए आजाद जैसे देशभक्ति प्रह्लासस्तंभ हैं। राष्ट्र के लिए अपने परिवार को दांव पर लगा देने का जज्बा उच्चतम राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्रीय गौरव व प्रगति का आधार है।

नेट की दुनिया पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कंटेंट एक जगह वेब भास्कर में...

Web Bhaskar

नॉलेज

अमेरिका से दुनिया में फैला नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट

अमेरिका में व्योमिंग, मोन्टाना और आयडाहो राज्यों के सीमा क्षेत्र में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना और देखरेख की शुरुआत एक मार्च 1872 को राष्ट्रपति यूलिसेस एस ग्रांट ने प्रस्ताव को कानून का रूप देकर की थी। यह अमेरिका का पहला नेशनल पार्क था। कई पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता यह नेशनल पार्क 22 लाख एकड़ (8,983 वर्ग किमी) से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। ऐसा कहा जाता है 11 हजार साल पहले मूल अमेरिकियों के पूर्वज येलोस्टोन के जंगलों में ही रहे थे। 1860 तक यहां कोई इवेंट नहीं हुआ। 1917 में पार्क की जिम्मेदारी नेशनल पार्क सर्विस को दे दी गई।



हेल्थ

कम समय में घर पर ही ऐसे कर सकते हैं वर्कआउट



यह हम सभी जानते हैं कि मोटापा हानिकारक होता है। उससे बचने या उसे खत्म करने के लिए वर्कआउट जरूरी है। हालांकि सभी लोग वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहां ऐसी कुछ स्टेप्स बताई जा रही हैं, जो सुबह के वक्त या रात में सोने से पहले घर पर कुछ ही देर में की जा सकती हैं। इससे न केवल मोटापा कम होगा, बल्कि शरीर भी चुस्त-दुरुस्त बना रहेगा। खासतौर से पेट कम करने में यह सहायक होगा।

• [pinterest.com](#)

जीवन में खुशियों के लिए बनाते हैं नया परिवार

इंस्पिरेशनल

पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा के किगाली में 24 बच्चे एक-दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। उनकी परिोधर्ण होने वाली हैं, वे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इतने में 23 वर्षीय 'पिता' जीन क्लाउड नकुसी उन्हें समझाते हैं कि यदि वे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। यह सामान्य नहीं, नया परिवार है। उन लोगों का जो नरसंहार से पीड़ित हैं। अलग-अलग उग्र वाले इन युवाओं का डीएनए एक-दूसरे से नहीं मिलता। फिर भी सबने सामूहिक फैसला करके 23 साल के जीन क्लाउड को पिता माना।

यहां 1994 के नरसंहार में एथनिक रवांडन टुट्सिस समुदाय के 8 लाख लोग मारे गए थे। उन परिवारों के



ये बच्चे आज बड़े हो गए हैं और कालेज में पढ़ते हैं। 1996 में रवांडा की 12 यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने 'एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट जेनोसाइड सर्वाइवर' बनाया था। वर्तमान में इसके 43,397 सदस्य हैं। यह एसोसिएशन स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के 25-25- छात्रों का समूह बनाता है। उनमें से इच्छुक सदस्यों को ही माता या पिता चुना जाता है। इस तरह

बनता है उनका नया परिवार। इस तरह वे सभी एक-दूसरे की मदद करते हैं। नकुसी कहते हैं, ऐसा करने से बच्चों को परिवार जैसा अनुभव होता है और खुशियां मिलती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा के कालेज ऑफ एजुकेशन में ऐसे 21 परिवार हैं। देश के दूसरे इलाकों में पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों ऐसे परिवार बनाए गए हैं।

• [newtimes.co.w](#)

एंटरटेनमेंट

ऐसे भी होते हैं कुछ स्विमिंग पूल

जापान के कनाजावा में ऐसा अनोखा स्विमिंग पूल है, जिसमें उतरने के बावजूद आप गीले नहीं होंगे। यहां चल सकते हैं और पानी के अंदर होने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यह 21वीं सदी के म्यूजियम ऑफ आर्ट में स्थापित है। जब आप पूल के डेक पर होते हैं, तो वह गररा और पानी से भरा नजर आता है। लेकिन जैसे ही डुप्लेक्स गैलरी में उतरते हैं, चैन जल ही। इसे एक ऑर्टिस्ट लिन्डो जैर्निक ने तैयार किया है।



• [designrulz.com](#)

करंट अफेयर्स

भारत में हो रहे चुनाव की देख के भीतर-बाहर जैसी चर्चा हुई वह अजरअशित है। हालांकि, यह बहस नए आर्थिक या विदेश नीति संबंधी मॉडल पर होनी तो भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा फायदा होता।

नए आर्थिक मॉडल पर हो चुनावी बहस

■ **रहीस सिंह**



देश के भीतर और बाहर भारत के चुनाव और उसके संभावित नतीजों को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हुईं, शायद इससे पहले कभी देखी-सुनी नहीं गईं। पड़ोसी देशों को लगता है कि नतीजे भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं। वजह प्यूरिसर्च सेंटर द्वारा कराए सर्वे के परिणाम हैं, जिनके अनुसार भारत में 70 प्रतिशत लोग देश की वर्तमान दशा और दिशा से असंतुष्ट हैं। 63 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि दुनिया में देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। चूंकि भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ भाषणों में सुरक्षा मुद्दों पर सख्ती दिखाई है इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे देश को सॉफ्ट स्टेट की छवि से उबारेंगे।

इस वजह से न केवल पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश भी आशंकित हैं। पाकिस्तान की जेहादी ताकतों को उर है कि भारत अब हिंदूवादी एजेंडे पर चलने के साथ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। लेकिन सच यह है कि देश की परंपरागत विदेश नीति में बदलाव इतना आसान नहीं है। कई प्रकार के दबाव हैं जो सरकार को ऐसा करने से रोकेंगे। हां 'नो फर्स्ट यूज' का परमाणु सिद्धांत बदल सकता है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो वहां से आने वाले अवैध घुसपैठियों पर लगाम लग सकती है। मजे की बात है कि इन देशों के उद्यमी और प्रोफेशनल (विशेषकर युवा) इन आशंकाओं से इतफाक नहीं रखते।

बाकी दुनिया की नजर एक अलग ही तथ्य पर है। आज भारत में अरबपतियों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये अरबपति अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव रखते हैं या यूं कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा जमा चुके हैं। खास बात यह है कि इममें से अधिकांश अरबपतियों की पसंद मोदी हैं, जैसा कि प्यू रिसर्च का सर्वे बताता है। इसके पताबिंद देश के सौ सबसे धनी कॉर्पोरेट स्वामियों में से 74 की पसंद मोदी हैं। उन्हें लगता है कि कठोर और आक्रामक स्वभाव वाले मोदी श्रम कानूनों में बदलाव और सब्सिडी में कटौती जैसे कदम उठाकर बिजनेस को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

चूंकि भारतीय कॉर्पोरेट लॉबी अमेरिकी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हुई है इसलिए भारतीय कॉर्पोरेट की पसंद अमेरिकी कॉर्पोरेट की पसंद है। अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत ने इसके संकेत नवंबर 2013 से ही देने शुरू कर दिए थे जब गोल्डमैन सैक्स ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर 'अंडरवेट' से 'मॉर्केटवेट' कर दी थी। हां, वहां की सरकार सीधे-सीधे मोदी को कंधे पर नहीं बिठा सकती, क्योंकि इससे उसकी छ्त्रम नैतिकता खतरे में पड़ जाएगी। बहरहाल, यदि इस चुनाव में सार्थक बहरसें होती तो नेहरू-गुजराल मॉडल से भिन्न मॉडल आएगा? अफसोस यह कि जिस तरह की बहस हुई वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा को धक्का पहुंचाने वाली है।

-लेखक विदेश व आर्थिक मामलों के जानकार हैं।
raheessingh@gmail.com

दिवट

चाद रविचरण, 16 मई के बाद वहां (सरकार में) मनमोहन सिंह नहीं होंगे, जिन्हें आप सभी समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं। वहां वे होंगे, जिन्हें आपने वोट दिया है।

-**प्रीतीश नंदी**, वरिष्ठ पत्रकार

असम की हिंसा को किसी भी तरह हिन्दू और मुस्लिम से जोड़ना बेतुका तर्क है। यह हिंसा घुसपैठियों और स्थानीय बोडो समुदाय ने की है।

-**डॉ. राकेश सिन्हा**, नई दिल्ली

इमेजिन करें, जो असम में हुआ। अगर वह दिल्ली या मुंबई में होता तो ये चैनल वाले किस तरह इस हिंसा को आकोश के साथ दिखाते।

-**निगेल ब्रिटो**, गोवा

आज हमें महंगाई और गैस कीमतों के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। मगर हम इसमें उलझें हैं कि पिरंटोंका गांधी मोदी की बेटी जैसी हैं या नहीं।

-**राघव** (आप नेता)

जब गुजरात में चुनाव थे, तब चैनल वाले पत्थर उठाकर वहां विकास ढूंढते फिरते थे। उनका ये उत्साह अमेठी और रायबरेली में क्यों नहीं दिख रहा।

-**राहुल दुबे**, इलाहाबाद

हम अगर विदेशी कंपनियों के शीतल पेय त्याग दें तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। फलों की फसल से एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

-**सुरेश रांका**

लेसन ऑफ लाइफ : हर सुबह मैं नौद से उठता हूँ। खुद से कुछ बातें करता हूँ। मेरे जीवन में आज का दिन भी आश्चर्य और अनिश्चितता से भरा होगा और मैं निकल पड़ता हूँ।

-**शेखर कपूर**, अभिनेता

जब भाजपा और कांग्रेस 'आप' का वजूद स्वीकार ही नहीं रहे, तो फिर हमले क्यों करता रहे हैं। क्या उन्हें हार का डर है? क्या यही प्रजातंत्र है?

-**सोनिया बजाज**, मुंबई

-**नेशनल आइडिशनल न्यूज़मैन**

